

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 253 बेमेतरा, शुक्रवार 08 मई 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

पहला कॉलम

ओडिशा में ससुराल के घर के सामने धरने पर बैठी महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या

गंजम। ओडिशा के गंजाम जिले में एक गर्भवती महिला की कथित तौर पर निर्मम हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम उस समय दिया गया महिला जब महिला अपनी बेटी के हक की मांग को लेकर ससुराल में घर के सामने धरने पर बैठी थी. इस घटना ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया. पुलिस ने बताया कि मृतक और आरोपी की पहचान हो गई है. आरोपी शख्स महिला का देवर है. उसे हिरासत में लिया गया. वारदात के समय महिला का पति घर पर नहीं था. उस समय महिला अपनी 2 साल की बेटी के साथ ससुराल के घर के सामने धरने पर बैठी थी. बताया जाता है कि महिला का पति कुछ समय पहले उसे छोड़कर चला गया था. महिला अपनी बेटी के हक की मांग करते हुए अपने ससुराल घर के सामने धरना दे रही थी. पुलिस के अनुसार वह प्रेग्नेट भी थी. पुलिस के अनुसार मर्डर केस दर्ज कर लिया है

कश्मीर घूमने आए अमेरिकी नागरिक की श्रीनगर में मौत

श्रीनगर। कश्मीर घूमने आए एक 83 साल के अमेरिकी नागरिक की आज अचानक मौत हो गई. खबर के मुताबिक, वह सुबह श्रीनगर में डल झील के हाउसबोट में बेहोश होकर अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों ने मृतक की पहचान एंडरसन जॉन डेविड के तौर पर की है. वह अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के रहने वाले जॉन डेविड के बेटे थे. श्रीनगर में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मरने वाले के बीमार पड़ने पर हाउसबोट मालिकों और दूसरे लोगों ने उन्हें पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी पत्नी और एक और जान-पहचान वाले भी थे. अधिकारी ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें आते ही मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि शव को एसएमएचएस अस्पताल और बाद में आगे की कानूनी और मेडिकल प्रक्रिया के लिए शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में शिफ्ट कर दिया गया.

शशि शेखर वेम्पति सीबीएफसी के नए अध्यक्ष नियुक्त

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया विशेषज्ञ शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब भारतीय फिल्म का दायरा तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय सिनेमा, ओटीटी और वैश्विक सहयोग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में सेंसर बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। शशि शेखर भारत के प्रमुख मीडिया और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने प्रसार भारती के सीईओ पद पर अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उनकी अगुवाई में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया। इससे पहले वह इंप्रोसिस और डिजिटल न्यूज स्टार्टअप नीति डिजिटल से जुड़े थे। सार्वजनिक प्रसारण और डिजिटल नीति में उनके इसी योगदान को देखते हुए जनवरी, 2026 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था।

मेरे पीए की हत्या इसलिए हुई क्योंकि मैंने ममता को हराया

शुभेंदु अधिकारी ने पीए की हत्या को बताया सोची-समझी साजिश

नई दिल्ली/ एजेंसी

शुभेंदु अधिकारी ने अपने पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हरा दिया, इसलिए उन्होंने मेरे सहयोगी चंद्रनाथ रथ को मार दिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द गुनहगारों को पकड़ा जाएगा। पुलिस ने वह बाइक बरामद कर ली है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हमलावरों ने किया था। इस बाइक को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित मध्यमग्राम पुलिस थाने लाया गया है। सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि हमालवरों ने बहुत नजदीक से उन्हें गोली मारी है। जो भी हमलावर से उन्हें अच्छे से पता थी कि कहां गोली मारने से उनका तुरंत मौत हो जाएगी। अधिकारी ने बताया उनके शरीर से चार गोली निकली। यह हत्या पूरी तरह से नियोजन करके की गई है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम में बुधवार रात यह वारदात हुई। चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर चरमदीनों ने कई गंभीर खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि यह हमला पूरी तरह सोची-समझी साजिश थी। हमलावर 4 से 5 मोटरसाइकिलों पर सवार



होकर आए थे। उन्होंने चंद्रनाथ की कार का पीछा किया और दोहारिया इलाके में उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। चंद्रनाथ रथ भारतीय वायुसेना में सेवा देने के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद राजनीतिक सहयोगियों में से एक बन गए थे। 41 वर्षीय रथ मूल रूप से पूर्वी मेदिनीपुर जिले के चांदपुर के रहने वाले थे। यह वह राजनीतिक क्षेत्र था, जिसने बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी के उदय को आकार दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, शांत स्वभाव और चर्चाओं से दूर रहने वाले रथ, वर्षों से अधिकारी के करीबी समूह का हिस्सा होने के बावजूद बड़े पैमाने पर जमीन पर काम करते रहे। सक्रिय

राजनीतिक संगठनात्मक ढांचे में आने से पहले रथ ने रहरा राम कृष्ण मिशन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय वायुसेना में लगभग दो दशक बिताए थे। परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बार आध्यात्मिक जीवन पर विचार किया था और छात्र जीवन के दौरान रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों से वे काफी प्रभावित थे। वायुसेना से स्वीच्छक सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में थोड़े समय के लिए काम किया। इसके बाद वे धीरे-धीरे राजनीतिक समन्वय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में आगे बढ़े। शुभेंदु अधिकारी के परिवार की तरह ही उनका परिवार भी पहले तुणमूल कांग्रेस से जुड़ा था।

दोषियों को फांसी मत दो,चंद्रनाथ रथ की मां ने मांगी अנוखी सजा

पश्चिम बंगाल में एक बुधवार रात खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। मध्यमग्राम में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद चंद्रनाथ रथ के परिवार में मातम पसर गया है। चांदीपुर में पीए चंद्रनाथ रथ की मां हासिरानी रथ का रो-रोकर दुरा हाल हो गया। बेटे की मौत की खबर मिलते ही वे टूट गईं। चंद्रनाथ रथ की मां ने दोषियों को फांसी की सजा न देने की मांग की। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि दोषियों को सजा मिले। मैं एक माँ हूँ, मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी दी जाए। मैं उनके लिए आजीवन कारावास चाहती हूँ। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता बार-बार राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहे हैं। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के जो लोग तरह-तरह की भड़काऊ टिप्पणियाँ कर रहे थे, जो कह रहे थे कि 4 तरीख के बाद दिल्ली के 'बाप' भी हमें नहीं बचा पाएंगे, तो 4 तरीख के बाद उन्होंने वही कर दिखाया। अगर मेरे बेटे की मौत किसी दुर्घटना में हुई होती, तो मुझे इतना दुख नहीं होता।



ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा

13 जेट्स ढेर, 11 एयर फील्ड हुए ध्वस्त-एयर मार्शल एके भारती

नई दिल्ली। पिछले साल 7 मई 2025 को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम का एक बड़ा मिशन चलाया था। जिसकी आज पहली सालगिरह है। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पड़ोसी देश पाकिस्तान को हुए भारी नुकसान का आधिकारिक ब्यौरा पेश किया है। सैन्य अफसरों ने साफ कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ आतंकी अड्डों को खत्म करना ही नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को यह चेतावनी देना भी था कि अगर उसने भारत की सीमाओं या सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ की, तो भारत अब उसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकालते हुए सारे तथ्य रखे। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाया। इसके अलावा, पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमान पूरी तरह तबाह कर दिए गए। साथ ही, भारतीय सेना ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 300 किलोमीटर की दूरी से सटीक निशाना लगाकर दुश्मन



ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है

लेफ्टिनेंट जनरल घई ने बताया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' का असर अब भी कायम है। इसका मतलब यह है कि सेना ने इस मिशन से मिली सीख के बाद अपने काम करने के तरीके और रणनीतियों को तेजी से बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफतौर पर कहा कि अगर आगे कभी फिर से बड़े पैमाने की जरूरत पड़े तो भारतीय सेना उसके लिए पूरी तरह तैयार है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत का यह अभियान लगातार चलता रहेगा।

को ढेर किया। यह कामयाबी दिखाती है कि भारत की मिसाइल तकनीक आज कितनी आधुनिक और अचूक हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने जानकारी दी कि ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान और पीओके के भीतर स्थित 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया।

ग्वालियर में शादी से लौट रहे दोस्तों की कार बनी आग का गोला, 2 की मौत

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बुधवार को एक चलती कार में आग लग गई, जिससे उसमें सवार 2 लोग जिंदा जल गए। हादसा डाबरा इलाके में हुआ है। घटना के समय तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई, जिसके बाद उस पर बिजली के तार गिर पड़े। बताया जा रहा है कि 11केवी बिजली के खंभे से तार गिरने पर पूरी कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई छतरपुर निवासी अवधेश विश्वकर्मा (32) और रामजी सोनी (33) शिवपुरी आए थे।



उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए।

विजय को दूसरी बार राजभवन से वापस भेजा

अड़े राज्यपाल राजेंद्र-118 विधायक लाओ,तभी होगी शपथ

चेन्नई/ एजेंसी

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। टीवीके प्रमुख विजय आज एक बार फिर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर से मुलाकात की। हालांकि राज्यपाल ने साफ संकेत दे दिए हैं कि केवल सबसे बड़ी पार्टी होने भर से सरकार बनाने का रास्ता आसान नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल अपने रुख

पर कायम हैं कि विजय को पहले विधानसभा में बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा दिखाना होगा। राजभवन का मानना है कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में अस्थिर सरकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता, इसलिए 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का समर्थन साबित करना अनिवार्य होगा। दरअसल, 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें

जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया था। हालांकि विजय खुद दो सीटों से चुनाव जीते हैं और नियमों के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। ऐसे में पार्टी की प्रभावी संख्या 107 रह जाएगी। सरकार बनाने की कोशिश में टीवीके को उस समय बड़ी राहत मिली जब कांग्रेस ने डीएमके गठबंधन से अलग होकर विजय को समर्थन देने का फैसला किया। कांग्रेस के पांच विधायक टीवीके के



साथ आए, लेकिन इसके बाद भी आंकड़ा केवल 112 तक पहुंच पाया। यानी बहुमत के जादूई आंकड़े 118 से अभी भी छह विधायक कम

बिहार में हुआ कैबिनेट विस्तार

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कुल 32 मंत्रियों ने ली गोपनियता की शपथ

पटना/ एजेंसी



बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया पूरी की गई। पटना में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली कैबिनेट का विस्तार किया गया। गांधी मैदान में सम्राट चौधरी और उनकी कैबिनेट में कुल 32 मंत्रियों ने मंत्री पद और गोपनियता की शपथ ली। बिहार में कैबिनेट विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राजनाथ सिंह और कई अन्य नेता उपस्थित रहे। बिहार के लिए अहम चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, श्रवण कुमार, निशांत कुमार और लेसी सिंह को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इसी क्रम में रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाडगार, अशोक चौधरी ने शपथ ली। इसके अलावा पटना के गांधी मैदान में रमा

निषाद, रनेश सदा, कुमार शैलेन्द्र, शीला कुमारी, भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन सहनी, डॉ. संतोष कुमार सुमन, केदार प्रसाद गुप्ता और लखेन्द्र कुमार रौशन ने बिहार के मंत्री पद की शपथ ली। पटना में सुनील कुमार, श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, नंद किशोर राम, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और प्रमोद कुमार ने बिहार के मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने बाकी सभी पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है। विभागों के संबंध में, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता नीतीश कुमार मिलकर तय करेंगे कि किसे कौन सा विभाग और जिम्मेदारी मिलेगी। भाजपा से 15 और जेडीयू से 13 मंत्रियों ने शपथ ली। सहयोगी दल से 4 मंत्रियों ने ली शपथ।

जंगल से निकल रहा काला खजाना

सुरक्षा बलों की सर्चिंग में खुल रहे माओवादियों के गुप्त राज बस्तर में 50 करोड़ से ज्यादा पूंजी छिपे होने का अंदेशा है....



यह बरामदगी अंदरूनी इलाकों में छिपाकर रखे गए डंप से हुई है, जिनकी तलाश अभी भी जारी है। जानकार बताते हैं कि नोटबंदी के बाद माओवादियों ने रणनीति बदली

और नगद की जगह सोने में निवेश करना शुरू किया, ताकि जोखिम कम रहे। बरामद 8 किलो सोने की कीमत ही करीब 13 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिससे संगठन की

जालंधर में मचा हड़कंप

सीएम मान को भी मिली जान से मारने की धमकी

नई दिल्ली। मंगलवार को पंजाब में हुए दो धमाके के बाद एक बार फिर से गुरुवार को जालंधर में कई स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिलने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जालंधर के करीब 6 स्कूलों को ऐसे ई-मेल भेजे गए। इसमें बम धमाके और आत्मघाती कार हमले जैसी धमकियां दी गई हैं। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद से लोग दहशत में



आ गए हैं। बम धमाके की धमकी मिलने के बाद स्कूल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं। साथ ही एपीजे स्कूल ने एहतियात के तौर पर बच्चों की छुट्टी कर दी।

का कहना है कि राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल समर्थन पत्र या मौखिक दावे पर्याप्त नहीं होंगे। उन्हें 118 विधायकों का ठोस समर्थन चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बनने वाली सरकार स्थिर रहेगी और विधानसभा में बहुमत साबित कर सकेगी। इस बीच टीवीके नेता वीएस बाबू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ सकती है।

संपादकीय

नफरती भाषणों पर कानून क्यों बेअसर? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से उठे बड़े सवाल

हाल के वर्षों में कुछ नेताओं ने न केवल लोगों की भावनाएं भड़काने वाले भाषण दिए, बल्कि इस बात का खयाल रखना भी जरूरी नहीं समझा कि इससे देश में अलग-अलग समुदायों के बीच सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है और विषम हालात भी पैदा हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश की राजनीति में लोगों के बीच नफरत फैलाने वाले बयानों या भड़काऊ भाषणों के जरिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें चिंता का कारण बनती रही हैं। ऐसे अनेक मौके सामने आए, जिनमें किसी नेता पर राजनीतिक स्वातंत्र्य साधने या फायदा उठाने की मंशा से

ऐसी बयानबाजियां करने या नारे लगाने के आरोप लगे, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका पैदा हुई। मगर ऐसे नेताओं को जहां कानून के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, वहां उनके प्रति पुलिस या शासन-तंत्र ने एक तरह से नरम रवैया अपनाया। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर बढ़ते नफरती भाषणों की समस्या से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। मगर इस मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वर्तमान कानून का ढांचा लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को

ठेस पहुंचाने या सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली हरकतों से सक्षम तरीके से निपटता है। इसमें भारतीय दंड संहिता और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधान शामिल हैं। जाहिर है, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में अदालत ने एक तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है। मगर इससे इतर नफरती भाषणों के जरिए अगर लोगों के बीच विद्वेष फैलाने की कोशिश की जाती है, तो इसकी नए सिरे से व्याख्या करने और उसे कानूनी दायरे में लाने की जरूरत है। इस संदर्भ में अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराध की व्याख्या या उसे परिभाषित करना और सजा तय करना पूरी तरह विधायिका के

अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में अदालत केवल सुधारों की जरूरत की ओर विधायिका और कार्यपालिका का ध्यान खींच सकती है। अदालत की यह टिप्पणी अहम है कि नफरती भाषणों के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की शिकायत कानून के अभाव में नहीं, बल्कि उसके लागू होने में कमी से पैदा होती है। ऐसी शिकायतें आम रही हैं कि कानूनी प्रावधान होने के बावजूद कई मामलों में पुलिस या तो आरोपों की अनदेखी करती है या फिर कमजोर धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है। नतीजतन, जिन गतिविधियों की वजह से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी

चाहिए थी, उसके विरुद्ध कानून लाचार नजर आता है। दरअसल, हाल के वर्षों में कुछ नेताओं ने न केवल लोगों की भावनाएं भड़काने वाले भाषण दिए, बल्कि इस बात का खयाल रखना भी जरूरी नहीं समझा कि इससे देश में अलग-अलग समुदायों के बीच सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है और विषम हालात भी पैदा हो सकते हैं। मगर ऐसे आपत्तिजनक भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को लेकर सरकारों के भीतर ईमानदार इच्छाशक्ति का अभाव दिखता रहा है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह की प्रवृत्ति की अनदेखी करने या सुविधाजनक

तरीके से कुछ नेताओं के नफरती भाषणों के प्रति आंखें मूंद लेने का नुकसान आखिरकार आम जनता और देश को उठाना पड़ेगा। शीघ्र अदालत ने भी इसी संदर्भ में कहा कि नफरती भाषण और अफवाह फैलाने से जुड़े मुद्दे सीधे तौर पर भाईचारे, गरिमा और सैवधानिक व्यवस्था के संरक्षण से जुड़े हैं। कायदे से कुछ संवेदनशील स्थितियों के बावजूद अगर मौजूदा कानूनी प्रावधानों का दायरा सीमित है, तो यह केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे बदलते परिदृश्यों तथा चुनौतियों के मद्देनजर आगे किसी ठोस कानूनी उपाय की जरूरत पर विचार करें।

बोलने की भीड़ में खोती चुप्पी, आज मौन ही सबसे बड़ी समझदारी बन गया है

चुप्पी का यह रूप प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। उपनिषदों में कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी मौन रहकर ही बोलता है। यहां चुप्पी लिहाज का प्रतीक बन जाती है। जब कोई अप्रिय बात कही जा रही हो, जब बहस तीखी हो रही हो, तब शब्दों की बौछार करने के बजाय चुप रहना ही बुद्धिमत्ता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस राय को समर्थन देता है। कार्ल जंग ने कहा था कि मौन ही आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। आज के दौर में, जहां ‘ट्रोलिंग’ यानी किसी व्यक्ति को नाहक परेशान करना और विवाद खड़े करना सोशल मीडिया पर आम हैं, यह उक्ति हमें याद दिलाती है कि लिहाज बनाए रखना कितना कठिन, लेकिन आवश्यक है।

(अविनाश जोशी)
जीवन की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शब्दों का बोलबाला है। सामान्य भागीदारी वाली बातचीत की सहजता के बजाय हर कोई अपनी बात कहने, अपनी राय थोपने और बहस में उतरने को आतुर रहता है। सोशल मीडिया के इस युग में चुप रहना एक अपराध-सा लगता है, मानो मौन वाक्यहीनता का प्रतीक बन गया हो। मगर क्या वास्तव में चुप्पी का अर्थ शब्दों की कमी है? गहराई से विचार करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पुरानी कहावत है- 'चुप हू तो मतलब ये नहीं कि लफ्ज कम है/ चुप हूं बस इसलिए कि लिहाज बाकी है।' यह पांक्ति न केवल व्यक्तिगत संयम की गहराई दर्शाती है, बल्कि मानवीय संबंधों में सम्मान, धैर्य और समझदारी की महत्ता को भी रेखांकित करती है। चुप्पी कभी दुर्बलता नहीं रही, बल्कि यह सबसे मजबूत प्रतिक्रिया होती है। खासतौर पर जब शब्दों से अधिक लिहाज की जरूरत महसूस हो।

चुप्पी का यह रूप प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। उपनिषदों में कहा गया है कि सच्चा ज्ञानी मौन रहकर ही बोलता है। यहां चुप्पी लिहाज का प्रतीक बन जाती है। जब कोई अप्रिय बात कही जा रही हो, जब बहस तीखी हो रही हो, तब शब्दों की बौछार करने के बजाय चुप रहना ही बुद्धिमत्ता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस राय को समर्थन देता है। कार्ल जंग ने कहा था कि मौन ही आत्मा की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। आज के दौर में, जहां ‘ट्रोलिंग’ यानी किसी व्यक्ति को नाहक परेशान करना और विवाद खड़े करना सोशल मीडिया पर आम हैं, यह उक्ति हमें याद दिलाती है कि लिहाज बनाए रखना कितना कठिन, लेकिन आवश्यक है।

संबंधों में चुप्पी के लिहाज पर गौर किया जा सकता है। परिवार में पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक हो, तो झगड़ा बढ़ाने के बजाय चुप रहना ही समझदारी है। माता-पिता बच्चों की जिद पर गुस्सा न होकर मौन धारण करते हैं, क्योंकि उनका लिहाज बच्चों के भावनाओं के प्रति है। दोस्ती में भी यही लागू होता है। जब मित्र गलती पर अड़ जाते, तो तीखे शब्दों से उसे नीचा दिखाने के बजाय चुप रहकर समय देने से रिश्ता मजबूत होता है।

समाज में भी यह सत्य प्रकट होता है। राजनेता, नेता या सामाजिक कार्यकर्ता जब विवादोत्पद मुद्दों पर चुप रहते हैं, तो लोग इसे कमजोरी समझते हैं। मगर सच्चाई यह है कि लिहाज बनाए रखने के लिए चुप्पी जरूरी होती है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी की संवेदनशीलता को एक उदाहरण माना

जा सकता है। सांप्रदायिक दंगों के समय विरोधस्वरूप या उसे खत्म करने के उद्देश्य से वे मौन व्रत में चले जाते थे। उनका लिहाज राष्ट्र के प्रति था और मानवता की रक्षा उनका पहला ध्येय था। आजादी की लड़ाई में भी जब ब्रिटिश अत्याचार चरम पर था, गांधीजी ने कई बार चुप्पी को हथियार बनाया। इसी तरह, राजस्थान की लोक संस्कृति में ‘मौन व्रत’ की परंपरा है। राजस्थानी समाज में बुजुर्ग अक्सर कहते हैं,

अपने पद, टीम और संगठन के प्रति। 'हावर्ड बिजनेस रिव्यू' के एक अध्ययन में पाया गया कि सक्रिय श्रोता प्रबंधक चालीस फीसद अधिक सफल होते हैं। चुप्पी यहां रणनीति बन जाती है। साहित्य और कला में चुप्पी को लिहाज की ऊंचाई के रूप में चित्रित किया गया है। कबीर ने कहा है- 'मौन बानी सब बानी से भली।' उनके दोहे चुप्पी की ताकत पर आधारित हैं। प्रेमचंद की कहानियों में गांव के गरीब किसान चुप रहकर अन्याय सहते

हो, तब चुप्पी कायराता बन जाती है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अत्याचार के खिलाफ चुप रहना अपने आप में अत्याचार है। इसलिए चुप्पी का चयन बुद्धिपूर्वक और विवेक के साथ करना चाहिए। लिहाज का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार है। योग में 'मौन चिंतन' सिखाया जाता है कि चुप रहकर अंतर्मन से संवाद करो। इससे निर्णय शुद्ध होते हैं। हालांकि आज के डिजिटल युग में चुप्पी चुनना और



‘चुप रहो, तो सम्मान बढ़ता है।’
जो व्यक्ति चुप रहकर सुनता है, वही सच्चा नेतृत्व दे पाता है: कार्यस्थल पर चुप्पी का महत्त्व और भी स्पष्ट है। कॉर्पोरेट दुनिया में, जहां प्रतिस्पर्धा तीव्र है, बैठक में हर कोई अपनी बात थोपाते है, लेकिन जो व्यक्ति चुप रहकर सुनता है, वही सच्चा नेतृत्व दे पाता है। अधिकारी की गलत नीति पर तुरंत विरोध करने वाले कर्मचारी जल्दी बाहर हो जाते हैं, जबकि चुप रहकर सही समय पर सुझाव देने वाले तर्कही पाते हैं। यह लिहाज है

हैं, क्योंकि उनका लिहाज समाज के प्रति है। मगर यह भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि समाज के प्रति लिहाज तभी न्यायपूर्ण हो सकती है, जब अन्याय के विरुद्ध चुप रहने के हालात अंततः न हो। राजस्थानी लोकगीतों में भी ‘मौन प्रेमी’ की कहानियां भरी पड़ी हैं, जहां नायक चुप रहकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। चित्रकला में भी मौन का चित्रण होता है।

फिर भी, चुप्पी की सीमाएं हैं। हर स्थिति में मौन उचित नहीं। जब अन्याय हो, जब निर्दोष पर अत्याचार

भी कठिन है। व्हाट्सएप समूह, फेसबुक बहसों में तुरंत जवाब देने का दबाव रहता है, लेकिन जो व्यक्ति सच पढ़ कर भी चुप रहता है, वही परिपक्व है। दरअसल, चुप्पी से हम अपने आपको, संबंधों को और समाज को संभालते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत विकास का साधन है, बल्कि सामाजिक शांति का आधार भी। यानी जब बहस छिड़े, तो सोचने की जरूरत है कि क्या शब्द जरूरी हैं, या चुप्पी का लिहाज ही काफी है! यह चुनाव ही जीवन को समृद्ध बनाता है।

अलग-थलग पड़ता भारत- ईरान युद्ध में उलझी विदेश नीति, महंगाई बनी सबसे बड़ी चिंता

अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध कोई दूर की लड़ाई नहीं है। यह परिदृश्य पश्चिम एशिया का है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के पड़ोस में है। लाखों भारतीय इस क्षेत्र में रहते और काम करते हैं। लाखों भारतीय शिया मुसलमानों का ईरान के लोगों के साथ गहरा संबंध है। कहा जाता है कि भारत का ईरान के साथ पारंपरिक रूप से लंबा और ऐतिहासिक संबंध रहा है। साथ ही यह दावा भी किया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के ईरान के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और आर्थिक संबंध स्थापित हुए हैं- उदाहरण के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास। मगर भाजपा सरकार के कार्यकाल में ये दावे कमजोर पड़ गए हैं। इसका एक कारण इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच घनिष्ठ मित्रता है।

(पी. चिदंबरम)
भारत का झुकाव इजराइल की ओर रहा है- हाल ही में भारत ने इजराइल की अलोचना से संबंधित ब्रिक्स देशों के मसविदा प्रस्ताव पर वीटो किया था। फिर भी, अमेरिका-इजराइल गठबंधन ने भारत को 'अलग' रखा है और इसके बजाय शांति वार्ता के लिए मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान को तरजीह दी। अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध कोई दूर की लड़ाई नहीं है। यह परिदृश्य पश्चिम एशिया का है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के पड़ोस में है। लाखों भारतीय इस क्षेत्र में रहते और काम करते हैं। लाखों भारतीय शिया मुसलमानों का ईरान के लोगों के साथ गहरा संबंध है। कहा जाता है कि भारत का ईरान के साथ पारंपरिक रूप से लंबा और ऐतिहासिक संबंध रहा है। साथ ही यह दावा भी किया जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के ईरान के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और आर्थिक संबंध स्थापित हुए हैं- उदाहरण के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास। मगर भाजपा सरकार के कार्यकाल में ये दावे कमजोर पड़ गए हैं। इसका एक कारण इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच घनिष्ठ मित्रता है। नहीं रही पहले जैसी साख: एक समय था, जब किसी भी संघर्ष की स्थिति में शांतिदूत के रूप में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। मगर, इस बार 28 फरवरी, 2026 को युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और इजराइल दोनों ने भारत से जानबूझकर दूरी बनाए रखी। जबकि ईरान समय-समय पर भारत को जानकारी देता रहा। भारत का झुकाव इजराइल की ओर रहा है- हाल ही में भारत ने इजराइल की अलोचना से संबंधित ब्रिक्स देशों के मसविदा प्रस्ताव पर वीटो किया था। फिर भी, अमेरिका-इजराइल गठबंधन ने भारत को 'अलग' रखा है और इसके बजाय शांति वार्ता के लिए मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान को तरजीह दी।

भारत अब यह दिखावा नहीं कर सकता कि पश्चिम एशिया में युद्ध से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसने दुनिया के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचाया है, विशेष रूप से उन देशों को, जिनका वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री हितों में महत्वपूर्ण स्थान है। आइए, 28 फरवरी, 2026 को युद्ध शुरू होने



के बाद से भारत के आर्थिक संकेतकों पर नजर डालें- दुनिया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों और धमकियों से वाकफ है। उनके इन दावों पर किसी ने विश्वास नहीं किया कि ईरान की वायुसेना और नौसेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है, या ईरान के पास अब कोई सैन्य सुरक्ति नहीं बची है, ईरान में 'सत्ता' बदल गई है (एक या दो बार?), या ईरान ने अमेरिकी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है, या (अलग-अलग समय पर) युद्धविराम हो गया है। ट्रंप युद्ध रोकेते हैं, उसे दोबारा शुरू करते हैं, और फिर विराम की घोषणा करते हैं। इस बीच, ईरान और लेबनान पर इजराइल हमले जारी रखता है, और ईरान

जवाबी कार्रवाई करता है। दुनिया जानती है कि 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध कभी रुका नहीं। **सब कुछ सामान्य नहीं:** सरकार का दावा है कि 'सब कुछ सामान्य है'। आरबीआइ युद्ध की कीमत और परिणामों के प्रति अधिक जागरूक प्रतीत होता है। अश्लैल के बुलेटिन में आरबीआइ ने 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर दबाव', 'ईंधन और खाद्य पदार्थों के कारण महंगाई', 'बांड से आय', 'विदेशी निवेश के प्रवाह में अस्थिरता' और 'आयात में मंदी' का उल्लेख किया तथा चेतावनी दी कि 'यदि संघर्ष जारी रहा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को शीघ्र बहाल नहीं किया गया, तो इससे घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं।' पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने के अलावा (संभवतः चुनावों के कारण) सरकार ने नाममात्र के ही कदम उठाए हैं। ऐसा लगता है कि सरकार एक मूकदर्शक बनकर घटनाक्रमों को देख रही है। ऐसा लगता है कि सरकार एक मूकदर्शक बनकर घटनाक्रमों को देख रही है। ऐसा लगता है कि सरकार एक मूकदर्शक बनकर घटनाक्रमों को देख रही है।

भारत के लोग जुझारू और धैर्यवान हैं। वे जानते हैं कि सरकार से उन्हें बहुत कम मदद मिलने की उम्मीद है। वे अपनी नौकरियों और आय को बचाने के लिए चिंतित हैं। एलपीजी की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति की अनिश्चितता के कारण घरों तथा भोजनालयों में लकड़ी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। आम परिवारों ने खपत कम कर दी है और बचत पर जोर दे रहे हैं। ऊपरी तौर पर तो कोई व्यवधान या निराशा नहीं दिखती, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जाने पर लोगों की चिंता साफ झलकती है। प्रधानमंत्री चार राज्यों के विधानसभा चुनावों और सितंबर, 2023 में पारित महत्वा आरक्षण विधेयक को पुनः अधिनियमित कराने

के रणनीतिक अभियान में व्यस्त हैं। वे पांच मई के बाद ही शासन पर ध्यान दे सकते हैं। **सरकार और कदम उठा सकती है:** सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए और भी बहुत कुछ कर सकती है। *सरकार मनोरोग के तहत बकाया मजदूरी का भुगतान कर सकती है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के निरस्त होने और कथित रूप से पुनःलागू होने के बाद से अधर में लटकें कार्यक्रम को दोबारा शुरू कर सकती है। *शांति सड़क कार्यक्रम (पीएमजीएसवाई) में तेजी लाई जा सकती है और वर्ष 2026-27 में आबंटित 19,000 करोड़ रुपये में खर्च किए जा सकते हैं (2025-26 में बिना खर्च किए एप 6,871 करोड़ रुपए के विपरीत), और अधिक धनराशि आबंटित की जा सकती है। *वर्ष 2025-26 में पेयजल मिशन (जल जीवन) के लिए अनुमानित बजट 67,000 करोड़ रुपए था, लेकिन संशोधित बजट सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2026-27 के लिए बजट में निर्धारित 67,670 करोड़ रुपए अग्रिम रूप से आबंटित किए जा सकते हैं और राज्य सरकारों को तुरंत धनराशि जारी की जा सकती है। *कोविड महामारी के दौरान किए गए वादे (जिसे पूरा नहीं किया गया) के विपरीत सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने में हुए नुकसान की भरपाई के लिए स्पष्ट रूप से धनराशि निर्धारित करनी चाहिए तथा बैंकों को ऋण जल्द वितरित करने का निर्देश देना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र को गति मिल सके, जो अभी भी मंदी में है। निष्क्रिय बने रहने के बजाय, सार्वजनिक सुविधाओं के प्रावधान, रोजगार सृजन और लोगों की आय बढ़ाने पर ध्यान देना निश्चित रूप से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की कीमत एवं परिणामों से निपटने के लिए प्रभावी उपाय है।

